[Shri Rasabehari Behera]

to rural areas. What is the most relevant thing to the growth of sports is the need for bringing the large mass of rural population on the national mainstream. Organisation of sports and competitions at the Taluk and District level will have to be supplemented with a sincere effort to provide the necessary infrastructure like properly marked playing arenas or small utilisation sports complex (STADIA) supply of equipment for athletics, gymnastics and other sports materials which would generate enthusiasm of our people for the games and sports.

(iii) USE OF POWER ALCOHOL AS A SUBSTITUTE FOR DIESEL OIL FOR TRANSPORT VEHICLES.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): We are importing crude and diesel oil to an extent of Rs. 3,000 crores per annum which is becoming a great burden upon our economy.

It is learnt that in Brazil and other countries they are using power alcohol instead of diesel oil for transport vehicles. When I wanted to know from our Government during 1978-79 about our capacity of producing power alcohol they have said that we are having the technical know-how and capability to produce power alcohol.

We are having enough of molasses in our country and we can very easily manufacture power alcohol by using the existing sugar factories with slight modifications. If we can produce power alcohol, then, it is quite easy for us to reduce the import of diesel oil and we will be able to balance the payment position of the foreign trade.

Now it is published in the Press that sunflower oil can be used instead of diesel oil. We can utilise this process also to replace the use of diesel oil.

Our Government has to step up the research to find out whether the other edible oils can be used instead of diesel oil and methane can be extracted from some category of leaves to replace diesel oil.

(iv) NEED TO GEAR-UP PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM IN RAJASTHAN.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्न वक्तव्य सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं :—

"देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जिस प्रकार मजबूत करना चाहिये मजबूत नहीं किया जा रहा है । राजस्थान प्रान्त में सार्वजनिक वितरण प्रणाली टूटने की स्थिति में आ गई है । ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते अनाज की दुकानों में गेहूं उपलब्ध नहीं हो रहा है । राज्य में जो चावल भेजा गया है वह बहुत ही न्यूनतम क्वालिटी का है और बहुत ही मंहगा है । गेहूं के भाव 225 रुपये से ले कर 250 रुपये क्विटंल तक बढ़ गये हैं । राज्य में चीनी ग्रामीण क्षेत्रों में दो-दो माह तक और कहीं-कहीं तीन माह तक नहीं पहुंचती और राज्य को जन-संख्या के आधार पर पूरा कोटा नहीं मिलने से ग्रामीणों को 300 ग्राम से 400 ग्राम तक चीनी मिलती है । इसके अलावा और कोई आवश्यक वस्तुओं के बारे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित नहीं की गई है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ठीक प्रकार से क्रियान्वित न होने से ग्रामीण जनता में असंतोष है । यह प्रश्न अविलम्ब लोक महत्व का है ।

(v) REPAIR OF FAULTY TELEPHONES LINES BETWEEN BARUIPUR OTHER AREAS OF WEST BENGAL.

SHRI MUKUNDA MANDAL (Mathurapur): Mr. Chairman Sir, the people of Baruipur of West Bengal are facing hardship in contacting

Calcutta and other places over telephone because of cronic fault line between Baruipur and Calcutta. Being a developing town, it needs a constant communication link with the other places.

I, therefore, demand that the fault line should be repaired immediately so that local calls including trunk call service may be resumed and a S.T.D. link may be granted between Baruipur and New Delhi in order to cater to the need of this developing town. I also demand the improvement of telephone exchanges of Baruipur, Diamond Harbour and Kakdwip and the Minister should give a statement in the House in this matter.

16.19 hrs.

RAILWAY BUDGET 1980-81—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

श्री रामनगीना मिश्र (सलेमपुर) : मान्यवर, मैं आप का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप ने रेल बजट पर मुझे भी बोलने का अवसर दिया ।

कुछ कहने से पहले, रेल मंत्री जी के सम्बन्ध में जो हमारे पूर्ववक्ता श्री सत्यदेव सिंह जी ने प्रशस्ति की है, मैं अपने को उस से सम्बद्ध करता हूं क्योंकि समयाभाव के कारण पुनः उन शब्दों को कहना उचित नहीं है । वर्तमान बजट पर कुछ कहने से पहले मैं आप के माध्यम से सदन का ध्यान इस के पूर्व जो रेलों की क्षमता थी, उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । जिस वक्त इस देश की बागडोर माननीय इन्दिरा जी के हाथों में थी, उस समय 1976–77 में हर जगह रेलों की क्षमता के बारे में चारों तरफ से शोहरत थी ।

उस के बाद जब संयोग से इन्दिरा जी सत्ता से हटीं और जनता पार्टी का शासन आया तो उन तीन सालों में रेलवे में काफी गिरावट आयी । आंकड़ों से मालूम होगा कि 1977–78 में रेलवे के माल यातायात में कितनी गिरावट आयी । उस वर्ष 22 करोड़ 20 लाख टन का अनुमान था किन्तु 19 करोड़ 40 लाख टन का ही लदान सम्भव हो सका । उस के बाद इसका गंभीर असर पड़ा उसके अगले साल में । 1978–79 में 9001 डिब्बों का जहां औसत लदान था वह अप्रैल से दिसम्बर, 1979 तक घट कर 8644 माल डिब्बे रह गया ।

1977–78 में थर्मल बिजली घरों के लिये जहां 2578 डिब्बों का औसत लदान किया गया वहां 1978–79 में अप्रैल से दिसम्बर तक 2770 डिब्बों का औसत लदान किया गया । किन्तु जनवरी 1980 में यह लदान 2913 डिब्बे हो गया और फरवरी में बढ़ कर 3290 डिब्बों पर पहुंच गया ।

कहने का तात्पर्य यह है कि जनता पार्टी के शासन काल में तीन सालों में जो गिरावट आयी थी वह काफी दूर हुई । मान्यवर उस समय की हालत बहुत खराब थी । बिजली की देश में कमी थी और तमाम ट्रेनें बंद हो गयी थीं । जसा मैंने बताया कि थर्मल पावर को कोयले का लदान 1977–78 से बढ़ कर 1980 के जनवरी और फरवरी में 3290 डिब्बे तक पहुंच गया था ।

1977–78 में ट्रेनें अपने नियत समय पर नहीं चलती थीं लेकिन पहले जब इन्दिरा जी सत्ता में थीं और पंडित जी रेल मंत्री थे तो लोग रेलों से अपनी घड़ी का समय मिलाया करते थे । अगर वे पांच मिनट भी लेट हो जाते थे तो गाड़ियां छूट जाती थीं । जनता पार्टी के शासन काल में ट्रेनों में समय की